सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 584
06/08/2017

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की

पटना, 06 अगस्त 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में कल देर शाम तक ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने मनरेगा की समीक्षा करते हुये निर्देश दिया कि नालंदा जिला में मनरेगा अन्तर्गत कराये गए प्रोजेक्ट जल संचय को रोल मॉडल बनाते हुए इसे राज्य के सभी जिले विशेष कर दक्षिण बिहार के जिले में लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने सामाजिक वानिकी के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण कराने का निदेश दिया ताकि राज्य में वन आच्छादन में वृद्धि हो सके, साथ ही वंचित वर्ग, महिलाओं, वृद्ध, दिव्यांगों को वन पोषक के रूप में मनरेगा अन्तर्गत रोजगार मुहैया कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी सक्रिय मनरेगा मजदूरों का शत–प्रतिशत आधार सीडिंग दिसम्बर माह तक पूर्ण करने का निदेश दिया।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में 4555 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है तथा मार्च 2019 तक बिहार के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण की गुणवता एवं उपयोगिता हेतु थर्ड पार्टी द्वारा सत्यापन कराने की प्रक्रिया के बारे में कार्य योजना तैयार की जाय।

जीविका की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा इसे और व्यापक स्वरुप देने हेतु समूह गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए दिसम्बर 2018 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने परिवार के स्तर पर आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर "एकीकृत बकरी एवं भेड़ विकास योजना कार्यक्रम", "मुर्गी ग्राम योजना" एवं "समेकित गव्य विकास योजना" को व्यापक स्वरुप देने हेतु निदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री ने नीरा के उत्पादन एवं विपणन की सफलता को संज्ञान में लेते हुये राज्य स्तर पर विस्तारित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि जिन पात्र लाभुकों के पास वास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने विकास प्रबंधन संस्थान (Development Management Institute) की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसे विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु विभिन्न तरह के सामाजिक, नेतृत्व एवं आजीविका संवर्द्धन से संबंधित विषयों पर कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में विकास हेतु इस उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थान की नींव रखी गयी है, जो अपने आप में इसे विशिष्टता प्रदान करती है। इस संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग की भी समीक्षा की और विस्तृत दिशा–निर्देश दिये। उन्होंने खासकर पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को तीव्र गति से कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले दो वर्षों में सभी पंचायत सरकार भवन विहीन ग्राम पंचायतों में, भूमि की उपलब्धता के आधार पर, पंचायत सरकार भवन का निर्माण राज्य योजना मद से किया जाय। इस वर्ष वैसे पंचायतों को प्राथिमिकता दी जाएगी जहाँ भूमि उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन में सौर उर्जा की व्यवस्था भी करवाने हेतु विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने जिला परिषद् एवं पंचायत समिति की समीक्षा के क्रम में यह निदेश दिया गया कि कि जिला परिषदों के वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते इनकी सांस्थिक पुनर्गठन एवं सशक्तीकरण हेतु कार्रवाई की जाय तथा जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के आंतरिक निजी राजस्व की वृद्धि हेतु उपाय किए जायें।

समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों के मंत्री– ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार/पंचायती राज मंत्री श्री कपिलदेव कामत, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री अरविन्द चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

******